दक्षिण एशिया की वर्तमान समष्टि-आर्थिक चुनौतियां और नीतिगत प्राथमिकताएं*

शक्तिकान्त दास

दक्षिण एशिया में सुदृढ़, टिकाऊ और समावेशी संवृद्धि के रास्तों पर चर्चा हेतु आज यहां इस विशिष्ट सम्मेलन में शामिल होने के लिए आईएमएफ द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मुझे खुशी हो रही है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि सम्मेलन की कार्यवाही "साउथ एशियाज़ पाथ टू रेसिलिएंट ग्रोथ" नामक पुस्तक के शोध निष्कर्षों और नीतिगत सिफारिशों पर आधारित होगी। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, वैश्विक व्यापार और संवृद्धि दृष्टिकोण उत्साहहीन दिखाई देता है, और नीतियों को अनिश्चितता के बवंडर के बीच संचालित करना पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में, इस प्रकार के सम्मेलन हमें विकसित होते परिदृश्यों और नीतिगत उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। आज के अपने संबोधन में, मैं दक्षिण एशिया की वर्तमान समष्टि आर्थिक चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर अपने कुछ विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा।

इतिहास में पीछे मुड़कर देखें, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र विचारों, वाणिज्य, कला और संस्कृति आदि का एक प्रमुख केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, पृथ्वी पर तीन शुरुआती सभ्यताओं में से एक थी और सबसे व्यापक थी। तथाकथित मध्य युग में, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, जैसे- मसालों, कीमती धातुओं और अन्य खनिजों, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य फला-फूला था। कुल मिलाकर, दक्षिण एशियाई क्षेत्र का विश्व में सभ्यता और व्यापार की प्रगति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में, इस क्षेत्र में दुनिया की आबादी का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। 27 वर्ष की औसत आयु वाली यह दुनिया के सबसे युवा क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र की औसत संवृद्धि दर 1970 के दशक में 3 प्रतिशत से बढ़कर नवीनतम दशक (पूर्व-महामारी) में लगभग 7 प्रतिशत हो गई है। फलस्वरूप, प्रमुख संवृद्धि मानदंडों पर उल्लेखनीय प्रगति के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ा है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के नेतृत्व में दक्षिण एशिया, वैश्विक संवृद्धि में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान देता है। यह क्षेत्र दुनिया में कुल विप्रेषण प्रवाह का पांचवां हिस्सा भी प्राप्त करता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र अतीत में विकट वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए विकसित हुआ है। 1960 के दशक के खाद्य संकट के बाद, इस क्षेत्र ने हरित क्रांति को सफलतापूर्वक लागू किया। 1970 के तेल संकट के बाद, दक्षिण एशिया से पश्चिम एशिया में उत्प्रवासन, बाजार संचालित श्रम प्रवाहों में से एक था। बदले में, इस क्षेत्र में विप्रेषण (रेमिटेन्स) प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1997 के एशियाई वित्तीय संकट ने, दक्षिण एशियाई देशों को, पूंजी के बहिर्वाह में वृद्धि और विनिमय बाजार दबाव के रूप में, प्रभावित किया। इन वर्षों में, संकट निवारण रणनीति के रूप में, दक्षिण एशियाई देशों ने, ठोस समष्टि-आर्थिक नीतियों को प्राथमिकता देने के अलावा प्रतिस्पर्धा, विवेकपूर्ण विनियमन, बढ़ी हुई पारदर्शिता, लेखापरीक्षा और लेखा मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को अपनाया। इन उपायों ने, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्थाओं के समंजन के साथ-साथ समष्टिगत-स्थायित्व (मैक्रो-स्टेबलिटी) बनाए रखने में मदद की।

हाल के वर्षों में, कई आघातों - विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में युद्ध ने, दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह दक्षिण एशियाई क्षेत्र की भी आर्थिक संभावनाओं को धूमिल किया है। इस क्षेत्र के कुछ देश अधारणीय कर्ज़ और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न घटनाओं के असर से भी जूझ रहे हैं। नतीजतन, वे आईएमएफ की वित्तपोषण सुविधाओं का सहारा लेते रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, आईएमएफ के वैश्विक आर्थिक संभावना डेटाबेस (अक्टूबर 2022) के अनुसार, भारत, बांग्लादेश और मालदीव, 2022 और 2023 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं होंगी। एशियाई विकास बैंक के दिसंबर 2022 के दृष्टिकोण के अनुसार, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जीडीपी 2022 में

* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, का मुख्य भाषण - 06 जनवरी 2023 - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) एशिया एवं प्रशांत विभाग (एपीडी) और आईएमएफ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी), नई दिल्ली, द्वारा सह-आयोजित उच्च-स्तरीय सम्मेलन।

6.5 प्रतिशत और 2023 में 6.3 प्रतिशत के साथ बढ़ने का अनुमान है।

विश्व बैंक का अनुमान है कि क्षेत्रीय सहयोग इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए लाभकारी स्थिति हो सकती है[1]। उदाहरण के लिए, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल पांचवां हिस्सा है, जिसका अर्थ है 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक कमी। विश्व बैंक के आकलन से यह भी पता चलता है कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के लिए एक सामान्य बिजली बाजार, पूंजीगत लागत में 17 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत कर सकता है। परिवहन और रसद में निवेश, दक्षिण एशिया में पोत-परिवहन लागत को कम करने में मदद कर सकता है। दक्षिण एशिया पर आईएमएफ (2019) के एक अध्ययन के अनुसार, 2030 तक 150 मिलियन से अधिक लोग दक्षिण एशियाई श्रम बल में प्रवेश करेंगे। निर्भरता अनुपात लगभग दो दशकों तक घटने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र के मजबूत जनसांख्यिकीय लाभांश का संकेत देता है।

नीतिगत प्राथमिकताएं

अब मैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए कुछ वांछित नीतिगत प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहूंगा। मैंने ऐसी छह नीतिगत प्राथमिकताओं की पहचान की है।

मुद्रास्फीति को नरम रखना

कोविड के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखला अवरोध, यूक्रेन में युद्ध के बाद खाद्य और ऊर्जा संकट जैसे कई बाहरी आघात, और मौद्रिक नीति में सख्ती से उत्पन्न वित्तीय बाजार में अस्थिरता ने, दुनिया के अन्य भागों की तरह दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में निरंतर मूल्य दबाव डाला है। 2022 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान, दक्षिण एशिया में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति औसतन 20 प्रतिशत से अधिक रही। आयातित जीवाश्म ईंधन पर इस क्षेत्र की भारी निर्भरता ने इसे आयातित ईंधन मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील बना दिया है। सफल अपस्फीति के लिए लक्षित आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेपों के साथ-साथ विश्वसनीय मौद्रिक नीति कार्रवाइयां, राजकोषीय, व्यापार नीति और प्रशासनिक उपाय प्रमुख उपकरण बन गए हैं। जबकि जिंसों की कीमतों और आपूर्ति शृंखला की बाधाओं में हालिया नरमी से आगे चलकर मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलनी चाहिए, अगर मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रहती है तो संवृद्धि और निवेश की संभावनाओं के प्रति जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए, मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देना, इस क्षेत्र के लिए, वर्तमान संदर्भ में, इष्टतम नीतिगत विकल्प हो सकता है। तथापि, अपस्फीति के दृष्टिकोण को वैश्विक संवृद्धि और व्यापार गतिविधि के लिए बिगड़ती संभावनाओं के माहौल में संवृद्धि के प्रति बढ़ते जोखिमों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

विदेशी कर्ज़ जनित दुर्बलताओं का रोधन

हाल के वर्षों में विदेशी कर्ज़ में वृद्धि और उससे संबंधित कमजोरियों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के कई देशों में स्मष्टि-आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर दिया है। विदेशी कर्ज़, जो पूर्व-महामारी अवधि में निम्न और मध्यम-आय वाले देशों (जिसमें सभी दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं) में पहले से ही बढ़ा हुआ था, 2019 में यूएस$ 8.2 ट्रिलियन से बढ़कर 2021 में यूएस$ 9.3 ट्रिलियन हो गया - यूएस$ 1.1 ट्रिलियन की वृद्धि।

डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव (डीएसएसआई) की स्थापना, मई 2020 में जी20 द्वारा की गई थी। दिसंबर 2021 तक, अनुमानित यूएस$ 12.9 बिलियन की कर्ज़ चुकौती स्थगित कर दी गई थी। विश्व बैंक के अनुसार, 73 डीएसएसआई-पात्र देशों में से 60 प्रतिशत कर्ज़ संकट के अत्यधिक जोखिम में हैं या पहले से ही इसका अनुभव कर रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि, सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत कर्ज़ पर, सबसे गरीब देशों द्वारा कुल विदेशी कर्ज़ चुकौती भुगतान 2022 में 35 प्रतिशत बढ़कर 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है और बढ़ती वैश्विक ब्याज दरों और डीएसएसआई कर्ज़ चुकौती आस्थगन पर ब्याज की चक्रवृद्धि के कारण 2024 तक उच्च बना रह सकता है।

भले ही डीएसएसआई में निजी ऋणदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया था, परंतु उनकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है। 2010 और 2021 के बीच निम्न और मध्यम आय

[1] स्रोत: https://www.worldbank.org/en/programs/south-asia-regional-integration/overview

वाले देशों के ऋणदाता संघटन में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। लंबी अवधि के सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत कर्ज़ में निजी ऋणदाताओं द्वारा उधार देने की हिस्सेदारी 2021 में 61 प्रतिशत (2010 में 46 प्रतिशत) थी और बॉण्ड धारकों के लिए बकाया कर्ज का हिस्सा 2021 में 47 प्रतिशत (2010 में 29 प्रतिशत) था।

निजी उधारदाताओं और गैर-पेरिस क्लब के आधिकारिक ऋणदाताओं के पक्ष में समय के साथ ऋणदाता आधार में एक अलग बदलाव ने, कम आय वाले अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता (आईडीए)-पात्र ऋणी देशों के लिए, ऋण पुनर्रचना प्रक्रियाओं में एक नया आयाम जोड़ा है। गैर-पेरिस क्लब ऋणदाताओं के बकाया ऋण का हिस्सा 2010 में 42 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 68 प्रतिशत हो गया। निजी ऋणदाताओं पर बढ़ती निर्भरता ने कर्ज़ चुकौती लागत और कर्ज़ समाधान प्रयासों में ऋणदाता समन्वयन की जटिल को बढ़ा दिया है। 2010-2021 के दौरान, आधिकारिक ऋणदाताओं से ऋण की औसत परिपक्वता 26 वर्ष की तुलना में निजी ऋणदाताओं से ऋण की औसत परिपक्वता 12 वर्ष थी, जबकि निजी ऋणदाताओं से ऋण पर औसत ब्याज दर 5 प्रतिशत की तुलना में आधिकारिक ऋणदाताओं से ऋण पर औसत ब्याज 2 प्रतिशत थी।

बहुपक्षीय संगठनों, विशेष रूप से आईएमएफ और विश्व बैंक की भूमिका ऋण उपचार के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण हो जाती है, साथ ही ऋण आँकड़ों की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और विश्लेषण के तंत्र को भी मजबूत करती है ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और ऋण धारणीयता को बनाए रखा जा सके। क्षेत्र विशेष मैक्रो डायनेमिक्स, नीति प्रभावशीलता चुनौतियों और राष्ट्रों की आर्थिक आकांक्षाओं पर ध्यान देने के साथ इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण में आईएमएफ की भूमिका भी सहायक होगी।

उत्पादकता बढ़ाना

जहाँ, धारणीय और व्यापक आर्थिक समुत्थान, वर्तमान में नीतिगत केंद्र बना हुआ है, वहीं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं के संभावित संवृद्धि पथ को बढ़ाने के लिए गहन संरचनात्मक सुधार करने जरूरी हैं। आपूर्ति शृंखलाओं, हरित संक्रमण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चल रहे वैश्विक पुनर्गठन ने निवेश और संवृद्धि के नए अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन नए निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नीतिगत रूप से अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता होगी, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र, उन हिस्सों में नेतृत्व करे जो निकटस्थ क्षेत्रों पर बड़े सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जैसे: अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य।

इस संदर्भ में, मैं नीतिगत प्राथमिकता के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले, वांछनीय संरचनात्मक परिवर्तन के लिए संसाधन आबंटन में सुधार की आवश्यकता होगी, यथा - उत्पादन को, कम उत्पादक क्षेत्रों से उच्च उत्पादक क्षेत्रों में ले जाना और नवाचार को बढ़ावा देना। दूसरा, कौशल बेमेल दूर करने के लिए, जो संसाधनों के पुनराबंटन में एक प्रमुख बाधा है, शिक्षा और कौशल उन्नयन पर नीतिगत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र की अनुकूल जनसांख्यिकी के लिए यह आवश्यक होगा कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया श्रम-गहन हो। तीसरा, जहाँ मुक्त व्यापार और एफडीआई, प्रौद्योगिकी के प्रसार और उत्पादकता संवर्धन के लिए पारंपरिक रूप से अनुकूल रहे हैं, वहीं अनुसंधान और विकास पर इस क्षेत्र द्वारा निवेश भी वर्तमान निम्न स्तरों से बढ़ना चाहिए, और वैज्ञानिक अनुसंधान और स्टार्ट-अप के लिए नीतिगत वातावरण को और अधिक फायदेमंद बनाया जाना चाहिए। चौथा, भौतिक अवसंरचना में निवेश - ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार - जो उत्पादकता वृद्धि के प्रमुख चालक हैं, को बढ़ाना होगा।

डिजिटल क्रांति की समकालीन दुनिया में अवसंरचना में, स्केलेबिलिटी और लचीलेपन पर विशेष जोर के साथ डिजिटल अवसंरचना, यथा: डेटा सेंटर, सेलुलर टावर और फाइबर कनेक्टिविटी भी शामिल हैं। फिनटेक, ई-कॉमर्स, एड टेक, हेल्थ टेक और फूड टेक नए युग के संवृद्धि-प्रेरक हैं और इन्हें गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट कनेक्टिविटी और भरोसेमंद डिजिटल भुगतान साधनों की आवश्यकता है।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए सहयोग को मजबूत करना

दक्षिण एशियाई क्षेत्र, जीवाश्म ईंधन और आयातित ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह क्षेत्र अस्थिर तेल, गैस और

कोयले की कीमतों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार की गतिशीलता को चलाने में भू-राजनीतिक कारकों के प्रमुख प्रभाव को देखते हुए, इस क्षेत्र को ऊर्जा सहयोग व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि बाहरी आघातों के प्रति सुदृढ़ता बढ़ायी जा सके।

भारत और बांग्लादेश पहले ही दोनों देशों के पावर ग्रिड को समकालिक रूप से जोड़कर ऊर्जा क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना (आईबीएफपीपी) - पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और बांग्लादेश में पारबतीपुर को जोड़ने वाली 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन - में प्रति वर्ष एक मिलियन मीट्रिक टन के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने की क्षमता होगी। सहयोग के अन्य उदाहरणों में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक का परिवहन शामिल है। इसी तरह, सीमापार पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन और संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजनाएं, इस क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग की अपार संभावनाओं के प्रमाण हैं।

इस क्षेत्र में, परीक्षण प्रक्रियाओं, प्रदर्शन और संरक्षण मानकों, और बिजली उपकरणों के लिए लेबलिंग मानदंड में सामंजस्य लाने से, लागत बचत, दक्षता और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा जिससे क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्युत प्रणालियों के एकीकरण से सौर और पवन संसाधनों के विकास को गति मिलने के साथ, अप्रयुक्त अधिशेष जलविद्युत का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। इस क्षेत्र के देशों द्वारा ऊर्जा-कुशल उपकरणों की थोक खरीद और वितरण के कार्यक्रम शुरु किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सस्ती कीमत पर एलईडी बल्बों के वितरण के लिए उजाला (सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति) योजना है।

इस क्षेत्र में हरित अर्थव्यवस्था के लिए सहयोग

दक्षिण एशिया अपनी बड़ी आबादी और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के कारण जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। चरम जलवायु घटनाएं - बाढ़, सूखा, गर्मी की लहरें और बेमौसम बारिश - पिछली शताब्दी में बढ़ी हैं। 2018 और 2030 के बीच, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के अनुमानों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, वाहन बेड़े को हरा-भरा बनाने और भविष्य के भवन को हरा-भरा और जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के प्रति प्रत्यास्थ बनाने के लिए धन की आवश्यकता, केवल दक्षिण एशिया में ही क्रमश: यूएस$410 बिलियन, यूएस$670 बिलियन और यूएस$1.5 ट्रिलियन होगी। वित्तपोषण के अलावा, सफल हरित परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी और प्रमुख खनिजों तक पहुंच भी महत्वपूर्ण होगी। मजबूत क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली विनाशकारी जलवायु घटनाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। भारत ने वैश्विक पहल की अगुवाई की और 2019 में आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए एक गठबंधन शुरू किया। एक अन्य पहल - ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (जीईएपीपी) के साथ साझेदारी में इंटरनेशनल सोलर एलायंस (आईएसए) - दुनिया को सोलराइज़ करने का लक्ष्य रखता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र को उचित कीमत पर तीव्र हरित परिवर्तन के लिए सहयोग मजबूत करना चाहिए।

पर्यटन को बढ़ावा देना

पर्यटन, कुछ दक्षिण एशियाई देशों, जैसे: मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। एक क्षेत्र के रूप में, पर्यटन रोजगार का बड़ा सृजक है। पूरे क्षेत्र में पर्यटन की समृद्ध अप्रयुक्त क्षमता है। हाल की अवधि में, पर्यटन इस क्षेत्र में कुछ हद तक पुनर्जीवित हुआ है, लेकिन अभी भी पूर्व-कोविड स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अंतर-क्षेत्रीय पर्यटक प्रवाह भी संभावना सीमा से कम है। सामान्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर वाले देशों में फैले धार्मिक पर्यटन परिपथ (सर्किट), जैसी क्षेत्रीय पहल, साहसिक पर्यटन परिपथ और चिकित्सा/आध्यात्मिक/आयुर्वेद परिपथ, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और एक जीवंत क्षेत्रीय मूल्य शृंखला बनाने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष

2023 के लिए वैश्विक व्यापार संभावना सहित, दक्षिण एशिया में बेहतर अंत:क्षेत्रीय व्यापार इस क्षेत्र में संवृद्धि और रोजगार के

अवसरों को बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय बैंक के स्तर पर, इस क्षेत्र में सहयोग का एक प्रमुख आयाम, समान लक्ष्यों और चुनौतियों पर एक दूसरे से सीख रहा है, जैसे: अवसंरचना वित्तपोषण, डिजिटल वित्तीय समावेशन, सीमापार विप्रेषण लागत न्यूनीकरण (यूपीआई प्रणाली से जुड़कर) और अपरंपरागत मौद्रिक नीति। सीमापार व्यापार और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) का रुपया में निपटान क्षेत्र में जहां आरबीआई ने पहले ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, भविष्य में सहयोग के और क्षेत्र भी हो सकते हैं।

आज लोकार्पित की जाने वाली पुस्तक इस क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने और उचित नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से सामान्य समस्याओं के समाधान खोजने हेतु बहुत सारे नए विचार प्रदान करती है। मैं उन लेखकों के प्रयासों की सराहना करता हूं जिनके योगदान से यह पुस्तक संभव हो सकी। मुझे विश्वास है कि नीतिगत विकल्पों पर आज होने वाले विमर्शों से हमें दक्षिण एशियाई क्षेत्र के भविष्य की संभावनाओं को फिर से आकार देने में मदद मिलेगी।

धन्यवाद !